की शिनाख्त की गई है। इन क्षेत्रों में दून घाटी, आगरा-मथुरा क्षेत्र और दहानू शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक उद्योग के स्वरूप निहित प्रक्रिया, कच्चे माल और प्रयुक्त ईंधन की किस्म पर विचार करने के बाद उद्योगों को "हरा", "संतरी" और "लाल" तीन श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है। गैर-प्रदूषक उद्योग "हरा" की श्रेणी में आते हैं जबकि मध्यम श्रेणी का प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग "संतरी" की श्रेणी में आते हैं। इन श्रेणियों में आने वाली यूनिटों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों और पर्यावरणीय रक्षोपायों के साथ कार्य करने की अनुमति दी जाती है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग "लाल" की श्रेणी में आते हैं जिनको इन क्षेत्रों में स्थापित करने का निषेध है।

प्रदूषण को कम करने के लिए जारी किए गए दिशा-निदेशों में ईंधन की कतिपय किस्मों और मात्राओं, बहिःस्राव विसर्जन की मात्राओं, उपयोग और कर्मचारियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगाना शामिल है।

गुजरात में प्रदूषणरहित शहर

1014. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के कुछ शहरों को प्रदूषणरहित बनाने का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात के कुछ शहरों में प्रदूषणरहित वातावरण बनाने तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए उनका चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) गुजरात के कुछ शहरों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि गुजरात सहित देश में प्रदूषण की निगरानी, नियंत्रण और निवारण के चालू प्रयासों को सुदृढ़ किया गया है, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के तहत अहमदाबाद शहर से ऊपर की ओर बैठा तक के बीच साबरमती नदी के प्रदूषित भागों को सफाई कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

2. गुजरात में वापी और अंकलेश्वर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में शिनाखत की गई है और वापी के संबंध में औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से कार्य योजना तैयार की गई है।

3. गुजरात सहित चार औद्योगिक राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से "इण्डस्ट्रीयल पाल्यूशन कंट्रोल प्रोजक्ट" नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में शामिल मुख्य घटक हैं; प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सुदृढ़ीकरण, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए बड़े और मंझौले उद्योगों को ऋण तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों के समूहों के लिए सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने हेतु सहायता।

4. छोटे उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है।

5. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद बड़ौदा, सूरत, वापी, राजकोट और भडौंच के शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

6. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कृत्यक बलों का गठन किया गया है।

7. बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

8. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किये गये हैं।

9. उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं।

10. उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निदेश दिये गये हैं।

11. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते है।

12. केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के तहत सभी वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं।

13. जन-जागरुकता अभियान चलाए गये हैं।

Pollution by Transport Vehicles

1015. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether any study has been done on the effect of pollution from vehicular transport on the health of people;

(b) Which cities have pollution levels affecting people hazardously; and

(c) steps being taken to protect people from vehicular pollution ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS : (SHRI KAMAL NATH) : (a) No comprehensive and conclusive studies have been done in the country are available on the effect of pollution from vehicular traffic on the health of people at large.

(b) Vehicular and industrial emissions are the main causes of pollution in the cities. National Environment Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur has carried out ambient air quality monitoring in ten major cities of Indian viz. Ahmedabad, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Cochin, Madras and Nagpur in Collaboration with Central Pollution Control Board. According to the air quality survey, the levels of sulphur dioxide and nitrogen oxide in Delhi, Madras, Calcutta, Bombay are within the prescribed limits, while the level of suspended particulate matter in these cities are on the higher side, which is due to the natural dusty conditions and increasing density of vehicular traffic.

(c) The steps taken by the Government to control vehicular pollution include the following :

(i) Emission normals for both petrol and diesel driven vehicles have been notified under the Motor Vehicles Rules, 1989 and these are under implementation from 1990.

(ii) The Ministry of Surface Transport have advised the various State Transport Directorates to enforce these standards.

(iii) Lead content in petrol have been already brought down to a national average of 0.18 gm/litre. Efforts are being made to reduce their levels even further.

(iv) Public awareness compaigns have been launched on various measures to prevent and control pollution from vehicles.

(v) More stringent norms for vehicular emissions have been notified under the Central Motor Vehicles Rules in September 1993 which would come into effect from 1996.

(vi) Automobile manufacturers have been asked to develop and improve their technology to meet the more stringent standards for emissions from vehicles.

(vii) City planners are advised to incorporate in their plans the long-term requirements of city transportation.

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरणों का लगाया जाना

1016. **श्री ईशदत्त यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में, राज्यवार, कौन-कौन से कार्य किये गये हैं; और